यूपी में एनसीआर जैसी सुविधा वाला शहर बसेगा

प्रदेश के समग्र विकास को लेकर बनी योजनाएं नए वर्ष में मूर्त रूप लेती दिखाई देंगी। एनसीआर से भी आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से लैस एससीआर यानी नया शहर बसाने की तैयारी है। इसमें लखनऊ समेत हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले शामिल होंगे। राजधानी में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो का दूसरा चरण चारबाग रेलवे स्टेशन से बसंतकुंज की बीच शुरू होगा। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए पांच नई कंपनियां बनेंगी।

उम्मीदें 2025

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं वाला एक नया शहर बसाने जा रही है। इस शहर में ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से भी बेहतर होगा। छह जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाया जाएगा। इसकी बुनियाद तैयार की जा चुकी है। वर्ष 2025 में इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा।

प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की चाहता गांवों से निकलकर शहरों में बसने वाली हो गई है। हरकोई अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा देना चाहता है। इसके चलते लखनऊ में आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जमीनें कम होती जा रही हैं। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं होने से उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है व विश्व स्तर के स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए जमीनें तलाशी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बसाना चाहते हैं।

राजधानी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी के 27826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर नया एससीआर बसाया जाएगा। इसमें आने-जाने के लिए सिटी बस और मेट्रो रेल की सुविधाएं दी जाएंगी। वर्ष 2025 में एससीआर मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई देने लगेगा। इसके लिए प्राधिकरण बनाते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आवंटन की प्रकिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि एक साल के अंदर एससीआर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ता हुआ दिखाई देने लगेगा।

- स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए जमीन की तलाश
- 16 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाएंगे

हर छत पर दिखाई देगा सोलर प्लांट

राज्य सरकार अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश के अन्य 16 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने जा रही है। इसके लिए नक्शा पास करने के साथ सोलर प्लांट लगाने की अनिवार्यता को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भवन एवं विकास उपविधि में इसके लिए प्रावधान करने पर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि साल 2025 में इस संबंध में राज्य सरकार कैबिनेट से प्रस्ताव पास करते हुए इसे अनिवार्य बनाएगी। नए क्षेत्रों में जहां इसे अनिवार्य किया जाएगा, वहीं पुराने क्षेत्रों में बने भवनों पर इसे लगाने के लिए सुविधाए दी जाएगी।

लखनऊ में मेट्रो का होगा विस्तार

लखनऊ में अभी अमौसी एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक मेट्रो रेल चल रही है। साल 2025 में इसे विस्तार देने की योजना पर काम शुरू होगा। लखनऊ में फेस 2 यानी दूसरे चरण में चारबाग रेलवे स्टेशन से बसंतकुज की बीच 11.098 किलो मीटर पर मेट्रो रेल निर्माण होना है। चारबाग से बसंतकुंज के बीच कुल 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 7 भूमिगत एवं 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण में 5 साल का वक्त लगेगा एवं इसमें 5081 करोड़ की लागत आएगी। दूसरे चरण में मेट्रो रेल चारबाग रेलवे स्टेशन, गौतमबुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज होते हुए बसंतकुंज तक जाएगी। इसके साथ ही गोरखपुर में भी लाइट मेट्रो रेल चलने की दिशा में काम शुरू होगा।

पांच नई कंपनियों से सुधरेगी बिजली व्यवस्था

1-आगरा मथुरा विद्युत वितरण निगम
2-काशी विद्युत वितरण कंपनी
3-गोरखपुर विद्युत वितरण निगम
4-झांसी-कानपुर विद्युत वितरण निगम
5-प्रयागराज विद्युत वितरण निगम

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के हर क्षेत्र को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से 42 जिलों की बिजली व्यवस्था पीपीपी माडल पर देने जा रही है। इन पांच नई कंपनियों के जरिये 42 जिलों के उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी। जिस गति से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन और प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रहे हैं उससे यह उम्मीद की जा रही है कि नये साल में प्रदेश की बिजली वितरण के क्षेत्र में पांच नई कंपनियां काम करने लगेंगी। जिनकी कमान निजी औद्योगिक घरानों के हाथ में होगी। प्रदेश में पहले से निजी क्षेत्र में दो कंपनियां नोएडा पावर कंपनी लि. नोएडा में और टोरेंट कंपनी आगरा में बिजली वितरण का काम कर रही हैं। नये साल में निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या सात हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश सरकार के पास सिर्फ तीन कंपनियां मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को कानपुर रहेंगी जिनका पूरा प्रबंधन प्रदेश सरकार के पास रहेगा।

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनी नये साल 2025 में इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन जाएंगी। इन दोनों कंपनियों के मौजूदा कार्यक्षेत्र में पांच नई कंपनियां अस्तित्व में आ जाएंगी। जिनमें 51 फीसदी हिस्सेदारी के साथ पूरा प्रबंधन निजी हाथों में दिए जाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। नये साल की पहली तिमाही में ही पांच नई कंपनियों के गठन की प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है, जिसके लिए जनवरी में टेंडर निकालने की चर्चाएं हैं। लेकिन निजीकरण का बिजलीकर्मियों द्वारा पूरजोर विरोध किया जा रहा है। किसान यूनियन, आम उपभोक्ता और सभी श्रम संगठन भी बिजलीकर्मियों के आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। सरकार के सामने विरोध के इस बड़े समूह को मनाने और निजीकरण के पक्ष में करने की बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन सड़कों पर उतरा तो इसमें तमाम विपक्षी दल भी कूद पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में निजीकरण के फैसले से पीछे हटने की स्थिति बन जाएगी।

स्वास्थ्य सेक्टर में निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी वालों की सेहत के लिहाज से 2025 खास होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेशवासियों को कई सौगात मिलने वाली हैं। खासतौर से आपातकालीन सेवाओं को बेहतर करने पर सरकार का जोर है। एक ओर राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू में 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर आकार लेगा।

- केजीएमयू में 500 बेड का नया ट्रामा सेंटर बनेगा

वहीं दूसरी ओर कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और आगरा में नये ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। नये साल में एलायड हेल्थ काउंसिल का गठन भी हो जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य सेक्टर के द्वार खोलने की तैयारी है।

यह साल भी चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रहा। योगी सरकार की एक जिला-एक मेडिकल योजना के तहत प्रदेश के 13 जिलों को नये मेडिकल कॉलेज मिल गए। इन कॉलेजों में एमबीबीएस की 100-100 सीटों की अनुमति मिलने से प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की एमबीबीएस सीटों में इजाफा हो गया है।

इसके अलावा पीपीपी मोड और निजी क्षेत्र के कॉलेजों में भी 450 एमबीबीएस सीटों की बढ़ोत्तरी हो गई है। इन जिलों में इलाज की सुविधा बढ़ने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिहाज से भी यह बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।

नए साल पर 80 हजार सिपाहियों की भर्ती होगी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलायेगा। यह सम्भव होगा जनवरी-2025 में शुरू हो रहे महाकुम्भ से। यूपी पुलिस इस कुम्भ के लिए पहली बार सात स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अभूतपूर्ण होगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

वर्ष 2025 में यूपी पुलिस को करीब 80 हजार नए सिपाही मिल जाएंगे। कुछ पुरानी भर्तियों का परिणाम भी इसमें शामिल रहेगा। इन सिपाहियों के यूपी पुलिस महकमे में शामिल होने से विजिबल पुलिसिंग को बल मिलेगा। ट्रैफिक व्यवस्था और गश्त के लिए पुलिस बल की कमी नहीं होगी। साथ ही इनकी तैनाती से पुलिस का रिस्पांस टाइम भी पहले से बेहतर होगा। 60244 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रियां अंतिम चरण में चल रही है।

आधुनिक उपकरणों से लैस होगी पुलिस

यूपी पुलिस को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा और इसके लिए मार्च 2025 तक का समय निश्चित किया गया है। इसमें आधुनिक असलहे व बुलेट प्रूफ वाहन की खरीद फरीख्त भी शामिल है। यूपी पुलिस नए साल मे पहले से ज्यादा मजबूत होकर सुरक्षा के नए मानकों का प्रदर्शन करेगी।